

माननीय के. एस. तिवाना और एम. एम. पुंछी जे.जे. के

समक्ष

अरुण स्पिनिंग मिल्स, - याचिकाकर्ता।

बनाम

कलेक्टर और अन्य, - उत्तरदाता

सिविल रिट याचिका सं. 1980 का 3555

19 मई, 1981

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम (1944 का 1) - धारा 40 (2) - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 - नियम 173 (क्यू) और 225 - धारा 40 (2) में होने वाली 'कानूनी कार्यवाही' शब्द - क्या इसमें विभागीय (जुर्माना) कार्यवाही शामिल है - धारा 40 (2) में निर्धारित सीमा की पट्टी-क्या विभागीय कार्यवाहियों पर लागू होता है - नौकरों के आपराधिक कृत्यों के लिए परोक्ष दायित्व - क्या स्वामी पर थोपा जा सकता है।

और रूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 40 (2) में 'कानूनी कार्यवाही' जैसे सामान्य शब्दों से पहले 'मुकदमा' और 'अभियोजन' जैसे विशिष्ट शब्द आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि 'मुकदमा' और 'अभियोजन' का अर्थ कानून के दायरे में स्थापित कार्यवाही है और उनमें विभागीय कार्यवाही शामिल नहीं हो सकती है और न ही होगी, जिसे उचित अधिकारी द्वारा उसके समक्ष शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 40 (2) के प्रावधानों पर एजुस्टेड जेनेरिस का सिद्धांत लागू होता है, हालांकि 'कानूनी कार्यवाही' शब्द केवल उन कार्यवाहियों को कवर करने के लिए

हैं जिन्हें 'मुकदमा' या 'अभियोजन' की तरह कानून की अदालत के समक्ष स्थापित किया जाना है। एक विभागीय अधिकारी द्वारा शुरू की गई आंतरिक विभागीय कार्यवाही और विभागीय प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली "कानूनी कार्यवाही" नहीं होगी जो अधिनियम की धारा 40 (2) द्वारा कवर की जाती है। सामान्य तौर पर, यह एक 'कानूनी कार्यवाही' होगी, लेकिन अधिनियम की धारा 4Q (2) द्वारा परिकल्पित प्रकार की नहीं होगी। इसलिए, विभागीय कार्यवाही, जैसे जुर्माना कार्यवाही अधिनियम की धारा 40 (2) द्वारा कवर नहीं की जाती है और इसमें सीमा की सीमा ऐसी कार्यवाही के लिए आकर्षित नहीं होती है।  
(पैरा 10 और 11)।

*हैदराबाद ऑलविन मेटल वर्क्स लिमिटेड* बहुत। *केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हैदराबाद के कलेक्टर, 1978* कर एलआर 1959।

से असहमति जताई।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के टी0 नाइल 225 के अनुसार उनके स्थान से निर्यात योग्य वस्तुओं को हटाने का कार्य नियमों में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए उत्पादन या निर्माण या भंडारण, उत्पादक या निर्माता या गोदाम कीपर को इस तरह के निष्कासन के लिए जिम्मेदार बनाता है। इतना ही नहीं, उसे अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटाए जाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना है जैसे कि उसने सामान हटा दिया हो। स्वयं। दूसरे शब्दों में, एक निर्माता या निर्माता, नियमों के उल्लंघन के लिए कर सकता है। उनके द्वारा किए गए अपराधों और दंड के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत उत्तरदायी ठहराया जाए और साथ ही अध्याय VI और संबंधित नियमों के तहत जब्ती और दंड के सिविल अधिनिर्णय के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक कंपनी के खिलाफ उसके क्लर्क द्वारा किए गए गलत कामों के लिए इस सिद्धांत पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है कि नौकरों के आपराधिक कृत्यों के लिए परोक्ष दायित्व स्वामी पर नहीं थोपा जा सकता है। नियमों का नियम 225 स्पष्ट रूप से नियमों के उल्लंघन के लिए मास्टर को उत्तरदायी ठहराता है, हालांकि वास्तव में दूसरे द्वारा किया गया है।

(पैरा 13)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं और याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राहत दी जाए: -

- a. 1/19 जून के नोटिस अनुलग्नक "पी -2" को रद्द करें, 1973, दिनांक 20 फरवरी का आदेश, 1975 अनुलग्नक "पी-4" प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा पारित। 1, प्रतिवादी संख्या 10 का आदेश। 2 दिनांक 24 अप्रैल, 1979 अनुलग्नक "पी। 6" और आदेश अनुलग्नक "पी। 8" प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा पारित। 3 पर 21 वां मार्च 1980.
- b. प्रतिवादियों को 10,000 करोड़ रुपये की राशि वसूलने से रोका जाए। 50,000।

और / या

- c. कोई अन्य राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार होगा।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस याचिका पर निर्णय लंबित रहने तक 10,000 करोड़ रुपये की वसूली की जाए। 50,000 रुपये की राशि पर रोक लगाई जाए और प्रतिवादियों को याचिका के अनुलग्नक ों की प्रमाणित प्रतियों और नोटिस की सेवा से छूट दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील भागीरथ दास।

प्रतिवादी की ओर से गोपी चंद, एडवोकेट।

### निर्णय

एम. एम. पुंछी, जे. (मौखिक)।

एक. मेसर्स अरुण स्पिनिंग मिल्स, एक पंजीकृत साझेदारी कंपनी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय का रुख किया है। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

गया है। याचिका में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 (क्यू) के तहत दायर किया है। याचिकाकर्ता ने इस तरह का जुर्माना लगाए जाने को चुनौती दी है।

दो. इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता फर्म ऊनी और घटिया धागे के निर्माण में लगी हुई थी। याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 174 और 178 के तहत निर्धारित फॉर्म एल -4 में लाइसेंस प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता को नियमों के अध्याय VII-A के प्रावधानों के तहत शासित किया गया, जिसमें स्व-निष्कासन प्रक्रिया का प्रावधान था। फर्म जिसका अस्तित्व वर्ष 1960 से था, 1 अप्रैल, 1969 को एक साझेदारी विलेख के *माध्यम से* पुनर्गठित किया गया था, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक पी -1 है। इसके तहत पांच व्यक्ति अर्थात् श्री हीरा लाल मेहरा, हेम राज कपूर, कृष्ण कुमार खन्ना, अरुण कुमार कपूर और श्रीमती निर्मला कपूर भागीदार बने। श्री हीरा लाल मेहरा साझेदारी व्यवसाय के प्रबंध भागीदार बने। उनके पास फर्म के किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करने, बर्खास्त करने या निलंबित करने की पूरी शक्तियां थीं, और साझेदारी व्यवसाय का सामान्य नियंत्रण, प्रबंधन और प्रशासन भी उनके पास निहित था।

तीन. सितम्बर, 1970 के महीने में, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, दिल्ली ने फर्म के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और पाया कि याचिकाकर्ता अपने स्वयं के कार्यालय रिकॉर्ड और रेंज कार्यालय के लिए ट्रेजरी चालान की प्रतियों में जमा राशि के आंकड़ों को विकृत करके जालसाजी कर रहा था और केंद्रीय राजस्व से सरकार को धोखा दे रहा था। जिसे मासिक व्यक्तिगत खाता खाता विवरण के साथ भेजा गया था। यह निष्कर्ष निकला कि 1 मार्च, 1969 से 31 अगस्त, 1970 की

अवधि के दौरान, 46,695 रुपये की राशि कम जमा की गई थी और सितंबर, 1970 की अवधि के लिए, 3,695 रुपये की राशि भी कम जमा की गई थी, जबकि पहली उपर्युक्त अवधि के दौरान और बिना पी के घटिया धागे और ऊनी धागे की सफाई की गई थी। दूसरी उपर्युक्त अवधि के दौरान व्यक्तिगत बहीखाते में पर्याप्त शेष राशि- उन दो मामलों में, याचिकाकर्ता को दिनांक 19 जून, 1973 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसकी प्रति याचिकाकर्ता के अनुलग्नक पी -2 में है। नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने विशिष्ट दलील दी कि अधिनियम की धारा 40 (2) के तहत, विभाग द्वारा इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

कार्रवाई के कारण की तारीख से छह महीने की अवधि। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विभाग को कार्रवाई का कारण 24 सितंबर, 1970 को या उसके आसपास प्राप्त हुआ, जब फर्म के खातों का ऑडिट किया गया था और विसंगतियों का पता चला था जैसा कि कारण बताओ नोटिस अनुबंध पी -2 में उल्लेख किया गया है। गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ता-फर्म ने तर्क दिया कि भागीदारों को अपने क्लर्क श्री जवाहर लाल खन्ना द्वारा की गई शरारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इस प्रकार फर्म धोखाधड़ी से कहीं भी संबंधित नहीं थी या परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं थी। जवाब 28 दिसंबर, 1974 को भेजा गया था, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न है।

चार. इस दौरान सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भारत सरकार, अमृतसर ने 24 जुलाई, 1973 को तत्कालीन सह-भागीदारों, श्री हेम राज कपूर, कृष्ण कुमार खन्ना, अरुण कुमार कपूर और श्रीमती निर्मला कपूर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की। श्री जवाहर लाल खन्ना, क्लर्क को भी आरोपी बनाया गया था। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 468, 471, 468/471 के साथ धारा 120-बी

और धारा 34 और 109 के तहत दर्ज की गई थी। शिकायत दर्ज होने से पहले मैनेजिंग पार्टनर श्री हीरा लाल मेहरा की मौत हो गई थी। शिकायत लंबित रहने के दौरान क्लर्क श्री जवाहर लाल खन्ना की भी मृत्यु हो गई। अमृतसर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल, 1974 के अपने आदेश के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 40 (2) के तहत सीमा की सीमा लगाते हुए आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया। यह भी माना गया कि कथित अपराधों के संबंध में सबूतों की कमी थी और साथ ही<sup>®</sup> मामलों की जांच भी की गई थी। आपराधिक न्यायालय के फैसले को कारण बताओ नोटिस के जवाब में भी लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मामला पक्षों के बीच अंतिम हो गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ दंड की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है।

पाँच. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, दिल्ली-प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या उसके तर्कों से संतुष्ट नहीं थे और , 19/20 फरवरी, 1975 के अपने आदेश के *माध्यम से*, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक पी -4 है, अधिनियम के नियम 173 (क्यू) के तहत याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली - प्रतिवादी संख्या 2 ने 23/24 अप्रैल, 1979 को याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक पी -6 है। याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को भी 21 मार्च, 1980 को भारत संघ द्वारा खारिज कर दिया गया था (अनुलग्नक पी -8 की प्रति)। याचिकाकर्ता का अब दावा है कि कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी-2) और आदेश अनुलग्नक पी-4, पी-6 और पी-8 इस आधार पर अवैध, कानून में अस्थिर और अधिनियम के *दायरे से बाहर* हैं , इस आधार पर कि अधिनियम की धारा 40 (2) के तहत परिकल्पित परिसीमन की अवधि समाप्त हो गई थी और उपरोक्त धारा में 'कानूनी कार्यवाही' शब्द

विभागीय कार्यवाही को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक था। एक अन्य आधार यह निकाला गया है कि फर्म के क्लर्क श्री जवाहर लाल खन्ना ने फर्म के साथ-साथ सरकार को भी धोखा दिया था और चूंकि याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा नुकसान की भरपाई की गई थी, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि सरकार को धोखा देने का उसकी ओर से कोई आपराधिक इरादा नहीं था। संक्षेप में, यह दावा किया गया था कि दंड की कार्यवाही जो प्रकृति में अर्ध-आपराधिक थी, याचिकाकर्ता के खिलाफ फर्म के नौकर के आपराधिक कृत्यों के लिए संभावित परोक्ष दायित्व पर शुरू नहीं की जा सकती थी।

छः. रिट याचिका में ली गई याचिकाओं को खारिज करते हुए, प्रतिवादियों ने यह रुख अपनाया है कि अधिनियम की धारा 40 (2) में होने वाली 'कानूनी कार्यवाही' शब्द अधिनियम के तहत विभागीय कार्यवाही के दायरे में नहीं आता है। नहीं उठता। कहा जाता है कि फर्म के कर्मचारी श्री जवाहर लाल खन्ना को जिम्मेदार ठहराये गये दोषों का नियमों के नियम 225 में निहित विशिष्ट प्रावधानों के मद्देनजर कोई महत्व नहीं है, जो निर्माता या विनिर्माण पर दंड का भुगतान करने का दायित्व निर्धारित करता है जैसे कि उसने स्वयं अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करते हुए माल हटा दिया हो। आपराधिक न्यायालय के फैसले के प्रभाव को प्रतिवादियों पर कार्यवाही शुरू करने और दंड के आदेश पारित करने के लिए बाध्यकारी नहीं होने का सुझाव दिया गया था, जो आदेश वैध होने का दावा किया गया था।

सात. याचिकाकर्ता के वकील श्री भागीरथ दास ने सबसे पहले अधिनियम की धारा 40 (2) के प्रावधानों को सेवा में शामिल किया, ताकि कारण बताओ नोटिस जारी करने और लागू आदेश पारित करने में प्रतिवादियों के अधिकार क्षेत्र को बाहर किया जा सके। इस अधिनियम की धारा 40(2), जैसा कि यह 21 मई, 1973 को इसमें किए गए

संशोधन से पहले थी, 1973 के *केन्द्रीय अधिनियम 22 के तहत निम्नानुसार थी -*

आदेश में कहा गया है, "कार्रवाई के कारण से छह महीने की समाप्ति के बाद या शिकायत किए गए अधिनियम या आदेश की तारीख से अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

निर्विवाद रूप से, असंशोधित धारा, यदि बिल्कुल भी, वर्तमान विवाद की ओर आकर्षित होगी।

आठ. इस मामले में वकील ने दलील दी कि 'कानूनी कार्यवाही' शब्द में अधिनियम की धारा 40 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही शामिल होगी, जिसमें छह महीने की सीमा की सीमा तय की गई है। रिलायंस को उनके द्वारा *लोक अभियोजक, मद्रास बनाम मद्रास पर रखा गया था। आर. राजू और अन्य*, (1) ने तर्क दिया कि धारा 40 (2) केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले आदेश के लिए उपलब्ध थी। उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले का भी इस्तेमाल किया। *पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिमिटेड और एक अन्य*, (2) यह बताने के लिए कि उस मामले में 'मुकदमे' के साथ 'कानूनी कार्यवाही' शब्द को जोड़े जाने का मतलब है कार्यवाही का मतलब है इजुस्टेम जेनेरिस। उस मामले में, लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को कंपनी अधिनियम की धारा 171 की व्याख्या करने की आवश्यकता थी, जहां कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 171 में होने वाली "कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं" शब्द का



अर्थ है कि पहली बार की अदालत में मूल कार्यवाही। वाद के समान एक मुकदमे के समान, एक वाद के समान एक याचिका के माध्यम से शुरू किया गया। हमेशा के लिए, ...। काउंसिल में गवर्नर जनरल में संघीय न्यायालय शिरो-मणि शुगर मिल्स लिमिटेड, (3) ने श्रीमती, शुकांतला के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा कि धारा 171 में "या अन्य कानूनी कार्यवाही" शब्दों पर कोई संकीर्ण निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कंपनी अधिनियम की योजना ने उन्हें यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है। एस. वी. कौंडास्कर बनाम सुप्रीम कोर्ट का भी यही दृष्टिकोण था। वी. एम. देशपांडे, आयकर अधिकारी, कंपनी सर्कल 1 (8) बॉम्बे और अन्य, (4), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 की व्याख्या करते हुए, जहां संघीय न्यायालय द्वारा शिरोमणि शुगर मिल्स लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों से सहायता मांगी गई थी। उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर, विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि धारा 40 (2) में नियोजित भाषा पर 'एजुस्टेड जेनेरिस' का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही वाद या अभियोजन के अनुरूप कार्यवाहियों तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि इसमें विभागीय कार्यवाहियां भी शामिल होंगी।

नौ. हमने इस मामले के इस पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी अधिनियम के तहत क्रमशः संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त दो निर्देशों का उस मामले के लिए कोई महत्व नहीं हो सकता है जिससे हम संबंधित हैं। हमें अधिनियम की धारा 40(2) के उपबंधों की जांच करनी होगी और इसे उस संदर्भ में समझना होगा जिसमें इसे कहा गया है। जैसा कि मैक्सवेल में विधियों की व्याख्या पर नोट किया गया है, पृष्ठ 326-

7 (11 वां संस्करण)।

लेकिन, सामान्य शब्द जो एक ही प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करता है, उनसे अपना अर्थ लेता है और माना जाता है कि यह उन शब्दों के समान जीनस तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में, इसे केवल एक ही तरह की चीजों या उनके द्वारा निर्दिष्ट चीजों को समझने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जब तक कि, निश्चित रूप से, यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि एक व्यापक अर्थ का इरादा था, उदाहरण के लिए, एक परंतुक विशेष रूप से कुछ वर्गों को छोड़कर स्पष्ट रूप से सुझाए गए जीनस के भीतर नहीं है। जब तक कि कोई न हो जीनस या श्रेणी में एजुस्टेम जेनेरिस सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए कोई जगह नहीं है।"

दस. यह स्पष्ट है कि 'मुकदमा' और 'अभियोजन' जैसे विशिष्ट शब्द सामान्य शब्दों 'कानूनी कार्यवाही' को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि 'मुकदमा' और 'अभियोजन' का अर्थ कानून की अदालत में स्थापित कार्यवाही है और उनमें विभागीय कार्यवाही शामिल नहीं हो सकती है और नहीं भी शामिल होगी, जिसे उचित अधिकारी द्वारा उसके समक्ष शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एजुस्टेम जेनेरिस का सिद्धांत उन प्रावधानों पर लागू होता है जिनसे हम संबंधित हैं, हालांकि 'कानूनी कार्यवाही' शब्द केवल उन कार्यवाहियों को कवर करने के लिए हैं जिन्हें 'मुकदमा' या 'अभियोजन' की तरह अदालत के कानून के समक्ष स्थापित किया जाना है। विभागीय अधिकारी द्वारा शुरू की गई आंतरिक विभागीय कार्यवाही और विभागीय प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली, हमारे विचार में, एक 'कानूनी कार्यवाही' नहीं होगी जो अधिनियम की धारा 40 (2) द्वारा

कवर की जाती है। आम बोलचाल की भाषा में, यह एक 'कानूनी कार्यवाही' होगी, लेकिन धारा 40 (2) द्वारा परिकल्पित नहीं होगी; अधिनियम के बारे में।

ग्यारह. मेसर्स हैदराबाद ऑलविन मेटल वर्क्स लिमिटेड में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दो फैसलों पर याचिकाकर्ता के वकील ने रिलायंस को रखा था। बहुत। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, हैदराबाद (5) और बी सत्य नारायण बनाम हैदराबाद भारत संघ और अन्य, (6), जिसमें इस तरह की विभागीय कार्यवाही को अधिनियम की धारा 40 (2) के मद्देनजर समयबद्ध माना गया था। पहला एकल पीठ का मामला था और उस पर बाद के मामले पर भरोसा किया गया था, जिसे एक खंडपीठ द्वारा तय किया गया था। ये आर राजू के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित थे। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, सतना बनाम सतना मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। भारत संघ और अन्य, (7), जिसमें यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 40 (2) पर एजुस्टेम जेनेरिस का नियम लागू होता है और सामान्य शब्द "अन्य कानूनी कार्यवाही" कानूनी कार्यवाही की समान श्रेणियों तक ही सीमित हैं, जिनमें से 'मुकदमा' और 'अभियोजन' उदाहरण हैं। यह इतने शब्दों में कहा गया है कि दंड की कार्यवाही जैसी विभागीय कार्यवाही अधिनियम की धारा 40 (2) के अंतर्गत नहीं आती है, और सीमा की सीमा नहीं लगाई गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जीप फ्लैशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इलाहाबाद मामले में फैसला सुनाया। भारत संघ और अन्य, (8) ने विचार किया कि अधिनियम की धारा 40 (2) में होने वाली 'अन्य कानूनी कार्यवाही' शब्द को अधिनियम के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को बाहर करने के लिए रखा जाना चाहिए। यह कर्तव्य की मात्रा और प्राप्ति का मामला था, न कि दंड की कार्यवाही का। भारत

सरकार के सचिव और अन्य मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले से भी समर्थन मांगा गया था । *लोगांडथन*, (9)। उस मामले में यह विचार लिया गया था कि कारण बताओ नोटिस के साथ शुरू की गई मूल्यांकन कार्यवाही अधिनियम की धारा 40 (2) के दायरे में नहीं थी, लेकिन अभियोजन के उद्देश्य से नहीं। इसी तरह, सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर और अन्य पर भरोसा किया गया था। *शिवा ग्लास वर्क्स लिमिटेड*, (10), जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने विचार किया कि "विभागीय कार्यवाही" शब्द को 'मुकदमे' जैसी कार्यवाही तक सीमित किया जाना चाहिए और 'अभियोजन', और विभागीय कार्यवाही दायरे से बाहर थी।

बारह. हमें इस विचार की प्रधानता प्रतीत होती है कि विभागीय कार्यवाही अधिनियम की धारा 40 (2) के दायरे से बाहर है। एकमात्र अंतर, जिसे हल्के से आग्रह किया गया था, वह यह था कि विभाग द्वारा शुरू की गई जुर्माना कार्यवाही एक अलग स्तर पर थी क्योंकि वे अभियोजन पक्ष के चरित्र का हिस्सा लेते थे। हम पाते हैं कि *मेसर्स हैदराबाद ऑलविन मेटल वर्क्स लिमिटेड के मामले* (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह "पूरी तरह से डिवीजन बेंच के फैसले पर आधारित है। हमें उस निर्णय को स्वीकार करने का लाभ नहीं मिला है, जिसका उल्लेख हमारे समक्ष किया गया था। इसके अलावा, *शिवा ग्लास वर्क्स लिमिटेड के मामले* (सुप्रा) में *कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड के मामले* (सुप्रा) में *मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय* के फैसले ने अधिनियम की धारा 40 (2) की ठोस विश्लेषण और तर्क के साथ व्याख्या की है, जिसके साथ हम सम्मानजनक समझौते में हैं क्योंकि यह हमारा अपना विचार है। इस प्रकार, हमें याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है कि अधिनियम

की धारा 40 (2) के मददेनजर उसे जारी कारण बताओ नोटिस या प्रतिवादियों के परिणामी आदेश उस दुर्बलता से ग्रस्त हैं।

तेरह. जहां तक अगले विवाद का संबंध है, नियमों के नियम 225 को लाभप्रद रूप से नोट किया जा सकता है:-

225. उत्पादक या निर्माता (किसी भी व्यक्ति) द्वारा माल को हटाने के लिए उत्तरदायी है - यदि कोई निर्यात योग्य माल इन नियमों में निर्धारित किसी शर्त का उल्लंघन करता है, जिसे (किसी भी व्यक्ति) द्वारा उस स्थान से हटा दिया जाता है जहां वे उत्पादित, निर्मित या गोदाम किए जाते हैं, तो उत्पादक या निर्माता या गोदाम के लाइसेंसधारक या रखवाले को इस तरह के निष्कासन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि उसने खुद सामान हटा दिया हो।

अन्य सभी नियमों की तरह यह नियम भी अधिनियम की धारा 38 से लिया गया है। अधिनियम की धारा 38 में संसद के समक्ष नियमों को रखने का प्रावधान है। यह विवादित नहीं है कि नियम ने संसद के अनुमोदन को पूरा किया। *एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड में। v- भारत संघ और अन्य* (11), सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुत्व अदालत ने पृष्ठ 635 पर बताया कि यदि कानून के तहत आवश्यक है कि इसके तहत बनाए गए नियमों को विधायिका के समक्ष रखा जाए, तो नियम स्वयं अधिनियम का एक हिस्सा बन जाता है। नियम 225 को संविधि का भाग मानते हुए, यह उल्लेखनीय है कि नियमों में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए उनके उत्पादन या निर्माण या भंडारण के स्थान से निर्यात योग्य वस्तुओं को हटाने का अधिनियम, उत्पादक या निर्माता या गोदाम के मालिक को इस तरह के निष्कासन के लिए

जिम्मेदार बनाता है। इतना ही नहीं, उसे उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए | अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाता है जैसे कि उसने खुद सामान हटा दिया हो। दूसरे शब्दों में, एक निर्माता या निर्माता, उनके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन के लिए, अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराधों और दंड के लिए उत्तरदायी हो सकता है और साथ ही अध्याय VI और संबंधित नियमों (तत्काल मामले में नियम 173 (क्यू) के तहत जब्ती और दंड के सिविल अधिनिर्णय के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। हमें विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता कि कंपनी के क्लर्क श्री जवाहर लाल खन्ना द्वारा किए गए गलत कामों के लिए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इस सिद्धांत पर कि नौकरों के आपराधिक कृत्यों के लिए परोक्ष दायित्व मालिकों पर नहीं थोपा जा सकता है। नियमों का नियम 225 स्पष्ट रूप से नियमों के उल्लंघन के लिए मास्टर को उत्तरदायी ठहराता है, हालांकि वास्तव में दूसरे द्वारा किया गया है।

चौदह. अंत में, यह था; याचिका में कहा गया है कि क्रिम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता-फर्म के भागीदारों के खिलाफ अभियोजन समय पर रोक था, सबूतों की कमी थी और मेंस रा का अभाव था | सीमा के बिंदु पर आपराधिक न्यायालय का निर्णय विभागीय अधिकारियों द्वारा समाप्त की गई दंड कार्यवाही के लिए रचनात्मक *प्रतिक्रिया* के रूप में काम नहीं कर सकता है, जैसा कि हमने बताया है कि ये दोनों अलग-अलग कार्यवाही हैं, जिनके अलग-अलग आयाम हैं- *आपराधिक* न्यायालय का निर्णय न्यायिक रूप से काम नहीं कर सकता है। नियमावली के नियम 225 के शासनादेश के दृष्टिगत विभागीय अधिकारियों के साथ। आपराधिक मामले में साक्ष्य की कमी के कारण, जिसके कारण भागीदारों को आरोपमुक्त किया जाना आवश्यक था, विभागीय अधिकारियों को दंड की कार्यवाही करने से वंचित नहीं

किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि एक फर्म कानून में एक इकाई या 'व्यक्ति' नहीं है, बल्कि केवल व्यक्तियों का एक संघ है और एक फर्म नाम केवल उन व्यक्तियों का एक सामूहिक नाम है जो फर्म का गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में, फर्म का नाम केवल एक अभिव्यक्ति है, केवल उन व्यक्तियों को नामित करने का एक जटिल तरीका है जो साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए सहमत हुए हैं। यह सच है कि आपराधिक अभियोजन सह-भागीदारों और सहकर्मियों के खिलाफ निर्देशित किया गया था।

उस फर्म के खिलाफ दंड की कार्यवाही का निर्देश दिया गया है जो थोड़ा सा भी अंतर नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने फर्म की अवधारणा को समझ लिया है (इस संबंध में देखें *दुलीचंद लक्ष्मीनारायण वी। आयकर आयुक्त, नागपुर*, (12)). यह भी उतना ही उल्लेखनीय है कि दंड की कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है और जुर्माना आमतौर पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि पार्टी ने या तो कानून की अवज्ञा में जानबूझकर काम नहीं किया या आचरण दूषित या बेईमान का दोषी था, या अपने दायित्व की सचेत अवहेलना में कार्य किया। सांविधिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं, यह प्राधिकरण के विवेकाधिकार का विषय है जिसका उपयोग न्यायिक रूप से और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने पर किया जाना चाहिए (इस संबंध में देखें *हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य* (13), *आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-1 और एक अन्य, v. अनवर अली*) (14) उपर्युक्त सिद्धांतों को आयकर कानून के न्यायिक दायरे में प्रतिपादित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उनके द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण के लिए कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है कि उनकी ओर से नियमों की कमी थी और किसी और ने उनकी जानकारी के बिना नियमों का उल्लंघन किया। काल्पनिक रूप से, जैसा कि नियमों के

नियम 225 में फर्म को प्रदान किया गया है और, उस मामले के लिए, भागीदारों ने नियमों का उल्लंघन किया था, जिससे जुर्माना लगाया गया था।

पंद्रह. पूर्वगामी कारणों के लिए, कुछ लोगों को इटपेटी में नोरिमेरिट 1 मिलता है, जिसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

*एस.सी.के.*

1. ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 2504.
2. ए.आई.आर. 1941 लाहौर 392.
3. ए.आई.आर. 1946 संघीय न्यायालय 16.
4. ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 878.
5. 1978 टैक्स एल.आर.1959
6. सी.डब्ल्यू.पी. 1974 का 2516.
7. 1977 टैक्स एल.आर. 1825.
8. 1979 ई. एल. टी. (जे. 674)।
9. (1976) द्वितीय एम.एल.जे. 295.
- 10.80 सी.डब्ल्यू.एन. 1057.
- 11.(1956) 29 आई.टी.आर. 535.



12.(1972) 883 आई.टी.आर. 26.

13.(1970) 76 आई.टी.आर. 696.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy